International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

''भारतीय विदेश नीति का बदलता स्वरूप : पड़ोसी देशों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन''

आशिक हुसैन खान[1]

रिसर्च स्कॉलर (राजनीति विज्ञान)

स्कूल ऑफ सोशल साईंसेस,

दे.अ.वि.वि. इन्दौर, (म.प्र.)

डॉ. संजू गांधी[2]

प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)

शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

झाबुआ, (म.प्र.)

- **सारांश** :

किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उसकी आंतरिक परिस्थितियां एवं बाह्य वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके साथ ही इतिहास, विरासत और विचारधाराओं का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। विदेश नीति एक प्रकार से रणनीतियों का समूह होता है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता तथा अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। भारत भी हमेशा से अपनी विदेश नीति संबंधित सिद्धांतों, तत्वों तथा विशेषताओं का पालन करते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों के दायरे में रहकर, वैश्विक शक्तियों एवं पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति में समय के साथ परिवर्तन हुआ है, जो एक आदर्शवादी एवं गुटनिरपेक्ष रूख से विकसित होकर एक अत्यधिक व्यावहारिक और मुखर दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुई है। हालांकि एक शान्तिपूर्ण और स्थिर पड़ोस बनाए रखने का मूल उद्देश्य अभी भी बना हुआ है, लेकिन नई भू–राजनीतिक वास्तविकताओं, विशेष रूप से इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए इसके तरीकों में बदलाव आया है, जो कि आवश्यक है।

- **संकेत शब्द** : विदेश नीति, राष्ट्रहित, पड़ोसी देश, आदर्शवाद, गुटनिरपेक्षता।

➢ प्रस्तावना :

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय विदेश नीति के शिल्पकार के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद और गुटनिरपेक्ष विशेषताओं को दृढ विश्वास से सम्मिलित किया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ था कि भारत शीत–युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ गठबंधन नहीं करेगा। इस नीति का उद्देश्य भारत की सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना और अपने आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना था। इस दौरान भारत का अपने पड़ोसियों के प्रति दृष्टिकोण अक्सर आदर्शवाद और ''बड़े भाई'' की

जिम्मेदारी की भावना पर आधारित था। जिसमें कभी–कभी तनाव भी पैदा होता था। 1962 भारत–चीन युद्ध एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के आदर्शवाद की विचारधारा को चकनाचूर कर दिया तथा भारत को अपनी सुरक्षा स्थिति को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया।

1990 के दशक के प्रारंभ में शीत–युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। भारत ने आर्थिक कूटनीति पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना शुरू किया और 'लुक ईस्ट नीति' के माध्यम से दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मज़बूत किया। इस नीति जिसे बाद में 'एक्ट ईस्ट नीति' में उन्नत किया गया हैं, का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक जुड़ाव के महत्व को स्वीकार करते हुए दक्षिण–प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ाना था। इसी अवधि में गुजराल सिद्धांत का भी उदय हुआ जिसने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए, विशेष रूप से छोटे पड़ोसी देशों के प्रति ग़ैर–पारस्परिकता और सद्भावना पर ज़ोर दिया।

➢ पड़ोसी प्रथम नीति :

आधुनिक भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता पड़ोसी प्रथम नीति हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर 2014 में स्पष्ट किया गया था। यह नीति एक रणनीतिक बदलाव है जो भारत के निकटतम पड़ोसियों जैसे– अफगानिस्तान, भूटान, मालद्वीप, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंधों को मज़बूत करने को प्राथमिकता देती है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो भौगोलिक रूप से भारत से दूर स्थित हैं परंतु भारत के उनके साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंध हैं, ये विस्तारित पड़ोसी देश हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण–पूर्वी एशिया या पश्चिम एशिया के देश हैं। वर्ष 2014 के बाद नई दिल्ली ने इन देशों के साथ व्यापक जुडाव पर ध्यान केन्द्रित किया हैं। क्षेत्र में 'आर्थिक सहयोग', 'विकास सहायता', तथा 'साझा चुनौतियों के समाधान' के माध्यम से संबंधों को मज़बूत करने के लिए 'पड़ोसी प्रथम' नीति को नवीन रूप प्रदान किया है। हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए भारत के भू–राजनीतिक ढांचे को 'सागर' के रूप में मान्यता दी हैं, जो क्षेत्र में सभी की सुरक्षा एवं विकास के लिए आवश्यक है।

➢ पड़ोसी प्रथम नीति की प्रासंगिकता :

अपने भू–सामरिक महत्व, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, आर्थिक हित आदि की दृष्टि से भारत की पड़ोस प्रथम नीति अधिक प्रासंगिक हैं। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ जैसे अलग–अलग बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं, साथ ही भारत को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसियों के साथ मज़बूत और स्थायी संबंधों की आवश्यकता है ताकि कोई भी पड़ोसी देश किसी भी विद्रोही समूह को भारत के खिलाफ अपनी भूमि तथा समुद्री सीमा का उपयोग करने की अनुमति न दें। सामुद्रिक पड़ोसी देशों यथा– मालद्वीप, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ सहयोग से भारत को अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र की

प्रभावी निगरानी में मदद मिलेगी। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उत्तरी पड़ोसी देशों जैसे– नेपाल व भूटान में जल–विद्युत की अपार क्षमताएं मौजूद है। इसके अलावा तेल एवं गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए हिंद महासागर के तटीय पड़ोसियों के साथ–साथ मध्य–पूर्व के विस्तारित पड़ोस का सहायोग प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है।

➢ **भारत की विदेश नीति का बदलता स्वरूप :**

भारतीय विदेश नीति का स्वरूप पड़ोसियों के प्रति बदल रहा है, जहां चीन की बढती चुनौती के बीच, भारत रक्षा, आर्थिक विकास और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है, जबकि भू–राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुपक्षीय कूटनीति, सामरिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर अधिक ज़ोर दे रहा हैं। भारत पड़ोस प्रथम नीति के तहत अपने पड़ोसियों के साथ साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यासों और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढाने के लिए सहयोगात्मक रक्षा समझौतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हैं। चीन के बढते प्रभाव और सीमाओं पर उसकी आक्रामकता को देखते हुए भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता जैसे बहुपक्षीय मंचों को सक्रिय रूप से बढावा दे रहा हैं, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। डोकलाम और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार में तेजी देखी गई हैं, वर्तमान में, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और वर्ष 2023–2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इस क्षेत्र में जटिल आर्थिक संबंधों को दर्शाता हैं। भारत और चीन अपनी कूटनीतिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहें हैं, इसलिए निरंतर संवाद, रणनीतिक परिपक्वता एवं सहकारी बहुपक्षवाद आवश्यक होगा। साझा हितों को वैश्विक जिम्मेदारियों के साथ जोड़कर, दोनों देश एक स्थिर, बहुध्रुवीय एशिया को आकार दे सकते हैं तथा अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकते हैं। भारत ने नेपाल में राजनीतिक उथल–पुथल के दौरान धैर्य और संयम का परिचय दिया हैं, और चीन को अपने प्रभाव बढाने के अवसर न देने का प्रयास किया हैं। भारत ने मालदीव एवं म्यांमार के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभ्यास और सहयोग को बढाया हैं। भारत ने कोविड–19 के दौरान अपने पड़ोसियों को वैक्सीन कूटनीति के तहत टीकें उपलब्ध कराएं हैं और 'ऑपरेशन दोस्त' जैसे अभियानों के माध्यम से आपदा राहत कार्य किए हैं।

भारत में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का जब गठन हुआ तो पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर की नियुक्ति विदेश मंत्री के पद पर हुई। इस पद पर नियुक्ति के बाद नए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत अपनी पहली विदेश यात्रा के लिये भूटान को चुना। भूटान के साथ भारत के संबंध सदियों से मधुर रहे हैं और यह भारत का करीबी सहयोगी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई हैं। विदेश मंत्री के इस दौरे से यह भी स्पष्ट हुआ कि निकट मित्र एवं पड़ोसी भूटान के साथ संबंधों को भारत कितना महत्व देता है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को ही चुना था। वर्ष 2019 में जब

प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली तो बिम्सटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे टीशेरिंग भी शामिल थे।

भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के संबंध में आतंकवाद का मुकाबला करने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर केन्द्रित रही, विशेषकर 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला और भारत–पाकिस्तान संघर्ष जैसी घटनाओं के बाद। भारत ने पाकिस्तान से स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उसके क्षेत्र का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों के लिए न किया जाए। इस संदर्भ में, अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया और भारत–अमेरिका ने संयुक्त वक्तव्य जारी किए। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ, जिसके बाद दोनों देशों ने युद्धविराम स्वीकार किया। 2025 के संघर्ष के दौरान द्विपक्षीय समुद्री व्यापार निलंबित कर दिया गया था। भारत का प्रयास रहा है कि दक्षिण एशिया में स्थिर और शान्तिपूर्ण संबंध बनाए रखे जाएं, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका पर भी ज़ोर दिया गया । भारत ने क्वॉड विदेश मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया।

- **पड़ोसी प्रथम की नीति कितनी कारगर :**

हाल के दिनों में भारत का अपने कई पड़ोसियों के साथ तकरार हुआ हैं। मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश इसके ताज़े उदाहरण हैं। मालदीव में राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मुईज़्ज़ू 'इण्डिया आऊट' के नारे पर चुनाव जीते थे। उसके बाद मुईज़्ज़ू ने दशकों से चली आ रही परम्परा को तोड़ दिया था। इस परम्परा के तहत मालदीव में सत्ता संभालने के बाद हर राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करता आया हैं, लेकिन मुईज़्ज़ू ने अपने पहले दौरे के लिए तुर्की को चुना। अपने चीन के दौरे के बाद मुईज़्ज़ू ने भारत से मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। भारत ने उनका अनुरोध मानते हुए अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। बाद में मुईज़्ज़ू के रवैये में थोड़ा परिवर्तन देखा गया और उन्होंनें भारत को अपना 'सबसे करीबी सहयोगी' बताया और आर्थिक मदद की मांग की। वर्ष 2020 में भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में भी कुछ इसी प्रकार की खटास आई थी। तब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा कोली ने कहा था कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा हैं, लेकिन 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार देखा गया हैं, इसका उदाहरण संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में नेपाली प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। बात अगर अफगानिस्तान के बारे में की जाए तो भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को वैद्यता प्रदान नहीं की है, हालांकि भारत उन पंद्रह देशों की सूची में शामिल हैं जो अफगानिस्तान में कूटनयिक मौजूदगी रखते हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत बैकफुट पर आ गया था। भारत के शेख हसीना की सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जब शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू हुए तो वहां के लोगों ने भारत को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। वर्तमान में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है लेकिन इसकी दिशा क्या होगी ये फिलहाल तय नहीं हैं।

कई जानकारों का मानना है कि अमेरिकी और रूस जैसे बड़े देशों के साथ संबंध बेहतर करने के क्रम में भारत ने अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों को तरजीह नहीं दी हैं। वरिष्ठ पत्रकार और 'द हिन्दू' की डिप्लोमेटिक पत्रकार सुहासिनी हैदर कहती हैं, ''अपने पड़ोसियों के संबंध कभी भी भारत के साथ अच्छे नहीं रहे हैं, बीते 10 वर्षों में सरकार ने 'नेबरहुड फर्स्ट' की बात की है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की हैं। इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए भारत को ये उम्मीद नहीं करना चाहिए की ये देश उसके बारे में अच्छा अनुभव करें।'' लेकिन बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रहीं वीना सिकरी ने कहा है कि देश की 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी काफी गतिशील हैं। वीना सिकरी का कहना हैं, ''ये नीति काफी उत्तरदायी और लचीली है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि कैसे भारत ने मालदीव में मुईज़्ज़ू की 'इण्डिया आऊट' नीति से निपटा। धीरे–धीरे ये सही हुआ।'' जब श्रीलंका बडे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब भारत ने वित्तीय मदद की। बांग्लादेश में भी भारत ने कहा कि वह अंतरिम सरकार के साथ काम करना चाहता हैं।'' उन्होनें कहा, ''यह एक बडा संकेत है कि–'नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी' अब विकसित और परिपक्व हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में इसका इम्तिहान हुआ है और ये उस परीक्षा में खरी उतरी हैं।''

➢ निष्कर्ष :

पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो देश की बदलती प्राथमिकताओं, रणनीतिक हितों और बदलती वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता हैं। भारत की 'पड़ोस प्रथम' की नीति का उद्देश्य निकटतम पड़ोसियों के साथ मज़बूत संबंधों को बढावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढावा देना और साझा चिंताओं का समाधान करना हैं। यह नीति भारत के परामर्शात्मक, ग़ैर–पारस्परिक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है। हालांकि, इस नीति को चीन के बढते प्रभाव, सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग में बाधाओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एक अधिक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

➢ **संदर्भ :**

1. पंत डॉ. पुष्पेश, जैन श्रीमाल, ''अंतर्राष्ट्रीय संबंध''।
2. फड़िया डॉ, बी. एल., फड़िया डॉ. कुलदीप, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा : 2020
3. दृष्टि आईएएस मैग़ज़ीन।
4. रिपोर्ट, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नई दिल्ली।
5. दत्त वी.पी., ''स्वतंत्र भारत की विदेश नीति'', नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया : 2009।
6. विज़न आईएएस मैग़ज़ीन।
7. मिश्रा राजेश, ''भारतीय विदेश नीति'' ऑरियंट ब्लैकस्वॉन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद : 2019।
8. सिंहल डॉ. रामप्रकाश, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा : 2017।
9. संस्कृति आईएएस मैग़ज़ीन।
10- https://www.bbc.com/hindi/articles/cdjexep77rgo
11- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/india-china-relations-crossroads-the-road-ahead
12- https://www.sanskritiias.com/hindi/current-affairs/indias-neighbourhood-first-policy-prospects-and-challenges
13- https://www.drishtiias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-discussions/neighbourhood-first-policy-india-bhutan-relations